मध्य प्रदेश को लिए एक मुश्त विकास सहायता

1319. **श्री अजीत जोगी :**

श्री छोटू भाई पटेल :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जून, 1989 में मध्य प्रदेश के लिए 5827 करोड़ रुपए की एक मुश्त विकास सहायता देने की घोषणा की थी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) योजना आयोग को किसी ऐसे पैकेज की जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

देश में प्रति व्यक्ति आय

1320. **श्री वीरेन जे. शाह :**

श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1990-91 की तुलना में वित्तीय वर्ष 1991-92 में देश की प्रति व्यक्ति आय में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 के दौरान देश में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी;

(ग) वर्ष 1991-92 में देश में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी;

(घ) क्या सरकार ने वर्ष 1992-93 की प्रथम छमाही के दौरान प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया है; और

(ङ) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि में प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े क्या रहे हैं और देश में वर्ष 1990-91 की तुलना में वर्ष 1991-92 के दौरान प्रति व्यक्ति आय के कम होने के कारण क्या हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां ।

(ख) 1980-81 की कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय (घटक लागत पर प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद) का 1990-91 के लिए 2199 रुपए का अनुमान लगाया गया था ।

(ग) 1991-92 के दौरान यह 2174 रुपए थी ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रति व्यक्ति आय में कमी का कारण सकल घरेलू उत्पाद (जी. डी. पी.) की वृद्धि में कमी होना था जिसमें 1991-92 में केवल 1.2% की वृद्धि हुई थी । फलस्वरूप, राष्ट्रीय आय में केवल 0.9% की वृद्धि हुई थी अर्थात् लगभग 2% जनसंख्या वृद्धि की तुलना में बहुत कम थी । पिछले वर्षों के मुकाबले सकल घरेलू उत्पाद (जी. डी. पी.) में वृद्धि मुख्यत: कृषि उत्पादन में 2.8% की कमी के कारण प्रभावित हुई थी । औद्योगिक उत्पादन में भी 0.1% की कमी हुई थी ।

World Bank's warning regarding rise in poverty

1321. SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN : Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in the Indian Express dated January 18, 1993 under the caption "WB warns nation of rise in poverty"; and

(b) if so, the reaction of Government to the criticism made by the World Bank on various issues mentioned therein ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO) : (a) Yes, Sir.

(b) Government is aware of the impact of contraction in the aggregate consumption. Every effort is made through growth

oriented policies and investment programmes to raise the rate of growth in GDP with which the level of consumption expenditure is related. Programmes to alleviate poverty by generating employment and enhancing the income of poor have been particularly strengthened. The network of the Public Distribution System (PDS) has been expanded over the years in order to increase availability of food to the poor. Government, in consultation with State Government and U.T. Administrations, have taken steps to revamp the Public Distribution System to improve its reach and to eliminate leakages or malpractices. Preference is now being given to the population living in most difficult areas of the country, such as drought prone areas, desert areas, tribal areas, certain designated hilly areas and urban slum areas. Eighth Plan has given a high priority to population control, literacy and human development.

पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए बोर्ड का गठन

132. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष एक अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए इस आशय का एक आश्वासन दिया गया था कि पहाड़ी राज्यों के विकास के लिए शीघ्र ही एक बोर्ड का गठन किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो इस आश्वासन को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) राज्य सभा में दिनांक 17-8-92 के तारांकित प्रश्न सं. 522 का उत्तर देते समय अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि उत्तर-पश्चिमी हिमालय के लिए अलग से पारिस्थितिकीय विकास प्राधिकरण के गठन का मामला विचाराधीन है ।

(ख) उत्तर-पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के लिए प्राधिकरण के गठन पर अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

उत्तर प्रदेश में जोत क्षेत्र की चकबन्दी में प्रगति

1323. **श्रीमती कैलाशपति** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उत्तर प्रदेश में जोत क्षेत्र के लिए की जा रही चकबन्दी का कार्य प्रगति पर है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो कितने जिलों में चकबन्दी का कार्य प्रगति पर है; और

(ग) क्या गढ़वाल में भी जोत क्षेत्र की चकबंदी का कार्य प्रगति पर है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Drought prone area programme in A.P.

1324. SHRI MENTAY PADMANABHAM : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) what is the present extent of Drought Prone Area Programme (DPAP) in Andhra Pradesh ;

(b) whether any assessment has been made of the implementation of DPAP in Andhra Pradesh ; and

(c) what further steps are under consideration to mitigate the effects of regular drought in some areas in Andhra Pradesh ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI RAMESHWAR THAKUR) : (a) Presently sixty nine blocks in the Districts of Anantpur, Chittoor, Cuddapah, Kurnool, Mahabubnagar, Nalgonda, Prakasam and Rangareddy are covered under the Drought Prone Areas Programme in Andhra Pradesh.

(b) The implementation of DPAP in all concerned States including Andhra Pradesh is being reviewed periodically by a Central Sanctioning Committee to assess the performance of the programme and provide suitable policy directions so as to improve it.